



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड—1

PART I—Section—1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 2014/भाद्र 14, 1936

No. 222]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 2014/BHADRA 14, 1936

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2014

सं. 7 (2)/ई-कोऑर्ड/2014.—सरकार ने व्यय प्रबंधन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

अध्यक्ष (अंशकालिक)	-	डॉ. विमल जालान, प्रख्यात अर्थशास्त्री/ लोक नीति विशेषज्ञ
सदस्य (पूर्णकालिक)	-	श्री सुमित बोस, पूर्व केन्द्रीय वित्त सचिव
सदस्य (अंशकालिक)	-	डॉ. सुबीर गोकर्ण, अर्थशास्त्री/लोक वित्त विशेषज्ञ
पदेन सदस्य	-	अपर सचिव (व्यय)
सदस्य-सचिव (पूर्णकालिक)	-	(अलग से अधिसूचित किया जाना है)

व्यय प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का दर्जा केन्द्रीय केबिनेट मंत्री का होगा।

2. व्यय प्रबंधन आयोग के विचारणीय विषय इस प्रकार होंगे:

- केन्द्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करने और राजकोषीय अनुशासन के प्रति वचनबद्धता से समझौता किए बगैर विकास संबंधी व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित राजकोषीय स्थल तैयार करने के तरीके सुझाना;
- पूर्ण राजकोषीय अनुशासन लागू करने के लिए बजट प्रक्रिया और एफआरबीएम नियमों सहित संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करना और उनमें सुधार के सुझाव देना;

- (iii) पूंजीगत व्यय पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ विद्यमान व्यय वर्गीकरण प्रणाली में आबंटन संबंधी दक्षताओं में सुधार के उपाय सुझाना;
- (iv) उपयोग, लक्ष्य और परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करके व्यय की प्रचालन संबंधी दक्षता में सुधार की रूपरेखा तैयार करना;
- (v) प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से सेवाओं पर व्यय के उचित भाग को पूरा करने के लिए एक कारगर रणनीति सुझाना;
- (vi) बेहतर नकद प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वित्तीय लागतों में कटौती के उपाय सुझाना;
- (vii) व्यय प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का अधिकाधिक प्रयोग सुझाना;
- (viii) लेखांकन, बजट प्रक्रिया आदि के संदर्भ में बेहतर वित्तीय सूचना प्रणाली सुझाना; और
- (ix) केन्द्र सरकार में लोक व्यय प्रबंधन से संबंधित किसी अन्य संगत मामले पर विचार करना और उपयुक्त सिफारिशें देना।

3. यह आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगा और किसी विशेष प्रयोजन के लिए यथा-आवश्यक ऐसे सलाहकार, संस्थागत परामर्शदाता और विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है। यह ऐसी सूचना मांग सकता है और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जो वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग, आयोग द्वारा यथा-अपेक्षित ऐसी सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे और ऐसी सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार विश्वास करती है कि राज्य सरकारें और अन्य संबंधित पक्ष आयोग को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

4. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. यह आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट 2015-16 के बजट से पहले और अपनी अंतिम रिपोर्ट 2016-17 के बजट से पहले प्रस्तुत करेगा।

रतन पी. वातल, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th September, 2014

No. 7 (2)/E. Coord/2014.—The Government has decided to constitute an Expenditure Management Commission comprising of the following :—

Chairman (Part Time)	-	Dr. Bimal Jalan, Eminent Economist/ Public Policy Expert
Member (Full Time)	-	Shri Sumit Bose Former Union Finance Secretary
Member (Part Time)	-	Dr. Subir Gokarn Economist/Public Finance Expert
Ex-Officio Member	-	Additional Secretary (Expenditure)
Member-Secretary (Full time)	-	(To be notified separately)

Chairman, Expenditure Management Commission will have the status of Union Cabinet Minister.

2. The Terms of Reference of the Expenditure Management Commission will be as follows:—

- i. Review the major areas of Central Government expenditure, and to suggest ways of creating fiscal space required to meet developmental expenditure needs, without compromising the commitment to fiscal discipline;
- ii. Review the institutional arrangement, including budgeting process and FRBM rules, for enforcing aggregate fiscal discipline and suggest improvements therein;
- iii. Suggest measures to improve allocative efficiencies in the existing expenditure classification system, including focus on capital expenditure;
- iv. Design a framework to improve operational efficiency of expenditures through focus on utilization, targets and outcomes;
- v. Suggest an effective strategy for meeting reasonable proportion of expenditure on services through user charges;
- vi. Suggest measures to achieve reduction in financial costs through better Cash Management System;
- vii. Suggest greater use of IT tools for expenditure management;
- viii. Suggest improved financial reporting systems in terms of accounting, budgeting, etc., and;
- ix. Consider any other relevant issue concerning Public Expenditure Management in Central Government and make suitable recommendations.

3. The Commission will devise its own procedures and may appoint such Advisors, Institutional Consultants and Experts, as necessary, for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and render such assistance as may be required by the Commission. The Government of India trusts the State Governments and others concerned will extend to the Commission full cooperation and assistance.

4. The Commission will have its Headquarters in Delhi.

5. The Commission will submit its interim report before the Budget of 2015-16 and its final report before the Budget of 2016-17.

RATAN P. WATAL, Secy.